ISSN 2231 - 4113

Śodha Pravāha

A Multidisciplinary Peer Reviewed Refereed Research Journal

Vol. 10, Issue II April 2020

Chief Editor
Dr. S. K. Tiwari
Editor
Dr. S. B. Poddar

- **'मानव अधिकारों के संरक्षण में नागरिको की प्रतिबद्धता'** 684-688
  डॉ. अनुपम शाही, एसोसिएट प्रोफेसर (राजनीति विज्ञान), हरिश्चन्द्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय, वाराणसी
  डॉ. अनुराधा राय, एसोसिएट प्रोफेसर (शिक्षा संकाय), हरिश्चन्द्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय, वाराणसी

- **श्रीमद्भगवद्गीता में योग और उसकी साधनानुशंसा** 689-691
  अभिनव कुमार पाण्डेय, शोधच्छात्र, वैदिक दर्शन विभाग, संस्कृतविद्याधर्मविज्ञान संकाय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी

- **रघुवीर सहाय के काव्य का समीक्षात्मक अध्ययन** 692-698
  विपिन कुमार मिश्र, शोधछात्र, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

- **उच्च शिक्षा में अनुसन्धान एवं नवाचार नये आयाम** 699-700
  डॉ. हरीश कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, इतिहास, राजकीय महाविद्यालय, सलेमपुर, देवरिया

- **उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की संवेगात्मक परिपक्वता का उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि के सन्दर्भ में अध्ययन** 701-705
  डॉ. चंद्रावती जोशी, एसोसिएट प्रोफेसर बी.एड विभाग ऍम. बी राजकीय पी जी महाविद्यालय हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखंड)
  शांति, एम. बी. राजकीय पी. जी. महाविद्यालय, हल्द्वानी जिला, नैनीताल (उत्तराखंड)

- **बंगाल के लोक संगीत की प्रमुख विधाओं का अध्ययन** 706-708
  डॉ. प्रमिति चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर संगीत, प्रयाग महिला विद्यापीठ डिग्री कॉलेज, प्रयागराज

- **मोदी युग में विदेश नीति का उभरता यथार्थवादी परिप्रेक्ष्य** 709-714
  डॉ. जयकुमार मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान, राजा हरपाल सिंह महाविद्यालय, सिंगरामऊ, जौनपुर (उ.प्र.)

- **एकात्म मानववाद : पं. दीनदयाल उपाध्याय जी के राजनीतिक विचारों की समीक्षा** 715-718
  डॉ. सरिता सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, डी.ए.बी. (पी.जी.) कॉलेज, देहरादुन

- **पालिशब्दानुशासने पाणिनेः प्रभावः** 719-720
  श्रवण दास स्वामी, गवेषकः, बौद्धदर्शनविभागः, सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयः, वाराणसी

- **विभिन्न वर्गों की शहरी व ग्रामीण छात्राओं में महिला सशक्तीकरण के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन** 721-728
  डॉ. हरीश चन्द्र, असि. प्रोफेसर, शिक्षा विभाग, आर.बी.एस. कॉलेज, आगरा

- **पूर्व मध्यकालीन सिक्कों पर विदेशी प्रभाव : प्रतिहारों के विशेष संदर्भ में** 729-730
  अमित कुमार दूबे, शोध छात्र, प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्त्व विभाग, आर्य महिला पी. जी. कॉलेज, चेतगंज, वाराणसी, सम्बद्ध काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी

- **सामाजिक वर्ग एवं मूल्य-विन्यास के सन्दर्भ में लखनऊ विश्वविद्यालय के विभिन्न शैक्षिक वर्ग के विद्यार्थियों की 'निष्पत्ति-आवश्यकता' का तुलनात्मक अध्ययन** 731-736
  डॉ. गीता रानी, एसोसिएट प्रोफेसर, शिक्षा शास्त्र विभाग, बी.एस.एन.वी.पी.जी. कॉलेज, लखनऊ

मोदी युग में विदेश नीति का उभरता यथार्थवादी परिप्रेक्ष्य

डॉ. जयकुमार मिश्र *

स्वतंत्रता के बाद से यदि भारतीय विदेश नीति का सम्यक विश्लेषण किया जाय तो ज्ञात होगा कि भारत की विदेश नीति राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने के लिए आदर्शवादी साधनों[1] पर बल देती रही है लेकिन जैसे ही राष्ट्रीय हितों का तालमेल आदर्शवादी साधनों के साथ बिगड़ने लगता था वैसे ही भारत के नेतृत्व–कर्त्ता समय की आवश्यकता और अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को भाँपकर यथार्थवादी विदेश नीति का रास्ता अपनाने से नहीं चूके। इंदिराजी द्वारा प्रथम परमाणु परीक्षण और बांग्लादेश का निर्माण हो या हो या राजीव गाँधी द्वारा श्रीलंका में भारतीय सेना भेजना हो या नरसिंह राव की लुक ईस्ट पॉलिसी हो या बाजपेयी जी का न्यूक्लियर–डॉक्ट्रिन हो या नरेन्द्र मोदी जी की 'पड़ोसी प्रथम' की नीति हो– इन सभी में यथार्थवादिता के दर्शन किए जा सकते हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की विदेश नीति को अन्य प्रधानमंत्रियों की विदेश नीति से अलग इसलिए रखा जा सकता है कि, इन्होंने भारत के ऊपर लगे 'सॉफ्ट नेशन' के लोगो को हटाने का सफल प्रयास किया है। आतंकवाद के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' की नीति को क्रियान्वित करते हुए म्यॉनमा में स्थित आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया गया। वस्तुतः 4 जून, 2015 को मणिपुर के चन्देल जिले में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैण्ड–खापलिंग गुट के आतंकवादियों ने भारतीय सेना के 6 डोगरा रेजीमेंट के जवानों पर घात लगाकर हमला किया, इसमें 18 जवान शहीद हुए, आतंकवादी इसके बाद पड़ोसी राज्य म्यॉनमा की सीमा मे चले गए। कारगिल युद्ध के बाद से यह भारत की सेना पर हुआ सबसे बड़ा हमला था। इसी रेजीमेंट की स्पेशल फोर्स ने 9 जून, 2015 को म्यॉनमा की सीमा में प्रवेश करके इस गुट के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 35 से अधिक आतंकवादियों को मार दिया[2] और इसी प्रकार 2–2 बार पाकिस्तान में घुसकर 'सर्जिकल स्ट्राइक'[3] करके यथार्थवादी विदेश नीति का स्पष्ट सन्देश दिया गया। यद्यपि सामान्य दृष्टि से देखने पर यह प्रतीत होता है कि, भारत ने अपने पंचशील के घोषित सिद्धान्त के विपरीत व्यवहार (अनाक्रमण और अहस्तक्षेप) किया है लेकिन लम्बे समय से निरन्तर घात लगाने वाले शत्रुओं से निबटने एवं राष्ट्रीय हितों के रक्षार्थ यह एक आवश्यक और सामयिक कदम था। मोदी ने आदर्शवादिता के मुखौटे को हटाकर यथार्थवादिता पर आधारित नए भारत की विदेश नीति को राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति का साधन बना दिया है। मोदी के प्रयासों का ही परिणाम है कि, इस्लामिक देशों के संगठन ओ. आइ. सी. ने 1–2 मार्च, 2019 को सम्पन्न अपने सम्मेलन में भारत को पहली बार विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में बुलाया। इस सम्मेलन में शामिल सभी इस्लामिक देशों के प्रतिनिधियों के समक्ष बोलते हुए तत्कालीन भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी ने 'धर्म प्ररित आतंकवाद' की निन्दा की और पूरी मानवता के लिए इसे अभिशाप बताया। इस सम्मेलन में किसी गैर–मुस्लिम देश के रूप में भारत ने पहली बार सहभागिता करके मुस्लिम देशों में अपनी स्वीकार्यता बढ़ने का प्रमाण दे दिया है। भारत को इस बैठक में बुलाए जाने से पाकिस्तान इतना नाराज हुआ कि उसने इस्लामिक देशों की बैठक में शामिल होने से ही इनकार कर दिया। इस्लामिक और अरब देशों के साथ सम्बन्धों को महत्वपूर्ण मानते हुए भी भारत ने 11 जून, 2019 को संयुक्त राष्ट्र की सामाजिक और आर्थिक परिषद (ECOSOC) में फिलिस्तीनी गैर सरकारी संगठन 'शहीद' को सलाहकार का दर्जा देने में इजराइल की आपत्ति के पक्ष में मतदान किया था क्योंकि इस संगठन ने इस्लामिक चरमपंथी संगठन हमास और हिजबुल्ला के साथ अपने सम्बन्धों के बारे में कोई भी स्पष्टीकरण देने से इनकार कर दिया था। आतंकवाद के प्रति भारत की 'जीरो टॉलरेंस' की नीति को अब विश्व के अन्य देश भी अपनी विदेश नीति के रूप में मानने लगे हैं, इसीलिए अमेरिका ने पुलवामा हमले के बाद भारत द्वारा किए गए सर्जिकल स्ट्राइक को 'काउन्टर–टेररिज्म–ऐक्शन' कहा। श्रीलंका[4]

---

* एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान, राजा हरपाल सिंह महाविद्यालय, सिंगरामऊ, जौनपुर (उ.प्र.)

और मालदीव[5] में भारत ने इसके पूर्व भी सैन्य हस्तक्षेप किया था लेकिन म्यानमॉ और पाकिस्तान में हुए सर्जिकल स्ट्राइक को महाशक्तियों द्वारा जिस सकारात्मक रूप में स्वीकार किया गया, उसे मोदी की विदेश नीति की स्वीकार्यता और भारत की बढ़ती क्षमता एवं आत्मविश्वास का प्रतीक है। आतंकवाद और घुसपैठ को निरन्तर प्रोत्साहन देने की अपनी नीति के बावजूद भी भारत ने पाकिस्तान के साथ करतारपुर कोरीडोर पर सफलतापूर्वक काम करके अपने सभी पड़ोसियों को मित्रता का स्पष्ट सन्देश दे दिया है। भारत ने महाशक्तियों के साथ अपने सम्बन्धों को एक नयी ऊँचाई देने के बाद भी 'बिग ब्रदर' की भूमिका निभाने का कोई भी प्रयास नहीं किया। पड़ोसियों के साथ अपने सम्बन्धों को पुनर्परिभाषित करने के लिए ही BIMSTEC को अधिक उपयोगी और व्यावहारिक बनाते हुए उसे पारस्परिक सहयोग के एक नए आधार के रूप में स्थापित किया है। 7–8 नवम्बर, 2019 को विशाखापत्तनम में इस संगठन के देशों के सम्मेलन में भारत ने संगठन के 'लैण्ड लॉक्ड' देशों को अपने बन्दरगाह की सुविधा देने का निर्णय किया। सदस्य देशों के बीच मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित करने, सड़क एवं जल परिवहन बढ़ाने, इण्टर–कनेक्टेड पॉवर ग्रिड का निर्माण करने और रिजनल डिजास्टर मॉनीटरिंग एण्ड वार्निंग स्स्टिम का विकास करने के लिए भारत प्रयत्नशील है।

चीन की **'स्ट्रिंज ऑफ पर्ल्स'**[6] की नीति का भारत जिस रणनीतिक रूप से उत्तर तैयार कर रहा है वह भी भारतीय विदेश नीति में आयी एक नयी यथार्थवादिता का ही प्रमाण है। प्रायः अपने सभी अन्तर्राष्ट्रीय भाषणों में नरेन्द्र मोदी नें टेक्नोलॉजी जनित नव उपनिवेशवाद और कर्ज आधारित उपनिवेशवाद (जैसा कि चीन ने श्रीलंका के हम्बनटोटा बन्दरगाह और पाकिस्तान के साथ 'वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी' के मामले में किया या अफ्रीकी महाद्वीप के देशों को भारी कर्ज देकर उनकी आर्थिक और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण खदानों को पट्टे पर लेकर कर रहा है) का सदैव विरोध करते रहे हैं। भारत अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण ढंग से बनाए रखने के प्रति संवैधानिक रूप से वचनबद्ध है (भारतीय संविधान का अनु. 51 ख), इसीलिए चीन की इस नीति के प्रति विश्व के देशों को जागरूक बनाने और अफ्रीकी देशों को भारत के करीब लाने के लिए ही भारत ने प्रथम बार सभी अफ्रीकी देशों का शिखर सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया और अफ्रीका के अत्यंत गरीब देशों को कर्ज देने की सीमा 50 मिलियन डालर की कर दी, भारत ने 20 अफ्रीकी देशों में अपनी मदद से कन्वेंशन सेंटर बनाने की भी घोषणा की। मोदी के प्रथम कार्यकाल (2014–19) में भारत के राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने कुल मिलाकर 29 बार अफ्रीकी देशों का दौरा किया। मोदी के इन प्रयासों का ही परिणाम है कि भारत आज अफ्रीका में 5वाँ सबसे बड़ा निवेशक और अफ्रीका तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक क्षेत्र बन गया है। मोदी के काल में भारत ने अफ्रीकी देशों के साथ सम्प्रभुता, समानता, सम्मान और उत्तरदायित्व पर आधारित एक नयी सहभागिता प्रारम्भ की है। इससे अफ्रीकी देशों के सामने चीन की सच्चाई भी उजागर हुई है। तंजानिया द्वारा चीन के 10 अरब डॉलर की एक बन्दरगाह परियोजना को शोषणमूलक कहते हुए निरस्त करना और सिएरालियोन द्वारा एक हवाईअड्डा परियोजना का निरस्तीकरण इसका प्रमाण है।[7] चीन को काउन्टर करने के लिए ही भारत ने ईरान के चाबहार में पोर्ट का निर्माण किया और म्यानमॉ के सितवे में 'विशेष आर्थिक क्षेत्र' की स्थापना की पहल की। **भारत–म्यानमॉ–थाइलैंड त्रिपक्षीय अन्तर्राष्ट्रीय राजमार्ग (1400 किमी.) का निर्माण चाइना–पाक–इकोनामिक–कोरीडोर का ही भारतीय प्रत्युत्तर है।** इसी प्रकार दक्षिण कोरिया और आस्ट्रेलिया के साथ होने वाली भारत की रणनीतिक वार्ताएं और जापान एवं अमेरिका के साथ होने वाली **2+2 वार्ताएं** (इसके अन्तर्गत भारत के विदेश और रक्षा मंत्री अमेरिका, आस्ट्रेलिया एवं जापान के अपने–अपने समकक्षों के साथ सामरिक मुददों पर बैठक करते हैं)[8] **इण्डो–पैसिफिक–रीजन में चीन को घेरने की भारत की नीति (एक नवीन शक्ति–संरचना तैयार करना) का ही हिस्सा है।** इस रीजन के अनेक देशों के साथ भारत ने सैन्य सम्बन्धों को मजबूत किया है और सैन्य युद्धाभ्यास प्रारंभ किए हैं। सियाम–2017 (18–24 मई 2017) और एक्सरसाइज मैत्री–2019 (भारत और थाइलैंड की सेनाओं के बीच युद्धाभ्यास, 16–19 सितंबर, 2019), सिम्बेक्स–2017 (भारत और सिंगापुर की सेनाओं के बीच युद्धाभ्यास, 18–24 मई, 2017), सीटमेक्स–2019 (भारत, सिंगापुर और थाइलैण्ड की सेनाओं के बीच

युद्धाभ्यास, 16–20 सितंबर 2019), आसिनडैक्स–2019 (2–16 अप्रैल, 2019 के बीच भारत और आस्ट्रेलिया के बीच सम्पन्न प्रथम युद्धाभ्यास), नोमैडिक एलीफैण्ट–2019 (भारत और मंगोलिया की सेनाओं के बीच होने वाला वार्षिक युद्धाभ्यास, 5–18 अक्टूबर, 2019), काजिंद–2019 (भारत और कजाकिस्तान की सेनाओं के बीच होने वाला युद्धाभ्यास, 3–15 अक्टूबर, 2019), एक्युवरिन–2019 (भारत और मालदीव के बीच होने वाला युद्धाभ्यास, 7–20 अक्टूबर, 2019), समूद्र शक्ति–2019 (भारत और इण्डोनेशिया की सेनाओं के बीच होने वाला युद्धाभ्यास), मालाबार श्रृंखला (भारत, जापान और अमेरिका की सेनाओं के बीच प्रतिवर्ष होने वाला सैन्य युद्धाभ्यास), मित्रशक्ति श्रृंखला (भारत और श्रीलंका के बीच प्रतिवर्ष होने वाला सैन्य युद्धाभ्यास) आदि इसके प्रमाण हैं। डोकलाम में चीन का जिस प्रकार भारत ने सामना किया है और दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते दबदबे को रोकने के लिए जिस प्रकार जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका (ये तीनो देश चीन के साथ नहीं हैं) के साथ अपने रणनीतिक सम्बन्ध मजबूत किए हैं, नागरिकता संशोधन बिल को लेकर मलेशिया के प्रधानमंत्री की टिप्पणी का भारत ने जिस प्रकार प्रत्युत्तर दिया है उससे आज पूरे विश्व में भारत की छवि एक सशक्त और सक्षम राष्ट्र के रूप में उभरी है। इससे विश्व की महाशक्तियाँ **भारत को चीन को रोकने वाली एक स्वाभाविक ताकत के रूप में देख रही हैं।** इस बात का प्रमाण **जी–7** की वायरिट्ज बैठक (फ्रांस, 24–26 अगस्त, 2019) में भारत को प्रथम बार **'वार्ता–भागीदार'** के रूप में शामिल होने के लिए मिला आमंत्रण है।

2017 में कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में **'शंघायी सहयोग संगठन'** (S.C.O.) **के सदस्य के रूप मे भारत को शामिल किया जाना भारत की वैश्विक शक्ति के रूप में चीन की स्वीकार्यता है** और यह मोदी कालीन भारतीय विदेश नीति की उपलब्धि है। 17 सितम्बर, 2021 को शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 21वीं बैठक ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में हाइब्रिड रूप में सम्पन्न हुई जिसमें भारत के विदेशमंत्री एस. जयशंकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया जबकि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एक विडियो लिंक के माध्यम से शिखर सम्मेलन को सम्बोधित किया। उन्होनें एस. सी.ओ. के व्यापक क्षेत्र में बढते कट्टरपंथ और उग्रवाद के कारण उत्पन्न होने वाली उन समस्याओं पर प्रकाश डाला जो इस क्षेत्र की उदारवादी और प्रगतिशील संस्कृतियों एवं मूल्यों वाले समाज की परम्पराओं के प्रतिकूल हैं। उन्होनें संयमित दृष्टिकोंण के साथ वैज्ञानिक तथा तर्कसंगत चिंतन को बढ़ावा देने के लिए एस.सी.ओ. से एक सार्थक एजेंडे पर काम करने का आह्वान भी किया।

9 सितंबर, 2021 का भारत की मेजबानी में 'ब्रिक्स' देशों के 13 वें शिखर सम्मेलन की ऑनलाइन बैठक में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने आतंकवाद के सभी प्रतिरूपों के प्रति असहयोग की बात कही। BRICS, BIMSTEC, ASEAN, शंघायी सहयोग संगठन और पूर्वी एशियाई देशों के सम्मेलन के माध्यम से भारत दक्षिण– दक्षिण सहयोग का एक नया अध्याय तैयार कर रहा है। 25 सितंबर, 2021 को संयुक्त राष्ट्र महासभा को सम्बोधित करते हुए श्री मादी ने हिन्द–प्रशान्त क्षेत्र में सैन्य दखल बढ़ा रहे चीन को संकेत करते हुए महासागरों को मानवजाति की 'साझी धरोहर' बताया। समुद्री संसाधनों का दुरूपयोग रोकने का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि, समुद्रों को सभी प्रकार के विस्तारवाद और सभी प्रकार के रोक–टोक से बचाने के लिए सभी देशों को आगे आना होगा। इसी क्रम में उन्होनें यू.एन.ओ के विस्तार की भी बात कही।

'ब्रिक्स', 'आसियान', और 'शंघाई सहयोग संगठन' जैसे मंचों को चीन के साथ साझा करने के बावजूद भी भारत चीन की विस्तारवादी नीतियों के प्रति पूरी तरह चौकन्ना है, इसका प्रमाण 'क्वाड' में भारत की उपस्थिति है। भारत की बढती आर्थिक–राजनीतिक–सामरिक शक्ति के कारण चीन को हिन्द–प्रशान्त क्षेत्र में घेरने की किसी भी रणनीति में अमेरिका या किसी भी देश के लिए भारत को साथ में लेना अपरिहार्य बन गया है। 24 सितंबर, 2021 को वाशिंगटन में सम्पन्न 'क्वाड' की प्रथम बैठक (जिसमें अमेरिका, भारत, जापान और आस्ट्रेलिया के शसनाध्यक्ष शामिल थे) में भारत ने हिन्द–प्रशान्त क्षेत्र में शांति स्थापना के प्रयासों को अपना प्रबल समर्थन देकर चीन को संकेत दिया कि, वह उस क्षेत्र में विस्तारवाद की प्रवृत्तियों को बढ़ावा न दे। चीन द्वारा 'क्वाड' को 'एशियाई नाटो'

कहने का उत्तर देते हुए भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि, 'क्वाड' एक ऐसा मंच है जहाँ चार देश अपने लाभ एवं विश्व की भलाई के लिए पारस्परिक सहयोग करने के लिए आए हैं। यह मंच पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन एवं आसियान जैसे क्षेत्रीय मंच के साथ मिलकर काम करने का एक अभिनव अवसर है और 'क्वाड' और 'नाटो' के बीच समानता ढूँढना बेबुनियाद है। अमेरिका का 'स्वाभाविक रणनीतिक साझीदार' भारत अमेरिका की नाराजगी की परवाह किए बिना रूस से एस.–400 मिसाइल प्रणाली खरीदता है और न तो अमेरिका तुर्की की तरह भारत पर कोई प्रतिबंध लगाता है[9] और न रूस ने ही चीन की मित्रता का इस सम्बन्ध में कोई घ्यान रखा। यह घटनाक्रम बताता है कि, भारत–रूस के सम्बन्धों में अब अमेरिका कोई 'फैक्टर' नही है, ये सम्बन्ध किसी दबाव से संचालित नही होते। वस्तुतः मोदी कालीन विदेश नीति की एक बड़ी उपलब्धि भारत की पूरे विश्व में सर्वस्वीकार्यता है, इसी ताकत के बल पर भारत आज एक यथार्थवादी और दूरगामी परिप्रेक्ष्य वाली विदेशनीति के मार्ग पर आगे बढ़ रहा हैं। इसका प्रमाण उपरोक्त वर्णित दृष्टांत है।

2021 में भारत के विदेश नीति की असली परीक्षा अफगानिस्तान के मुद्दे पर हुई। अगस्त में अमेरिका व सहयोगी देशों की सेनाओं की वापसी के बाद सत्ता अब तालिबान के हाथों में आ चुकी है। 7 सितंबर, 2021 को गठित अंतरिम सरकार के सभी मंत्री सक्रिय आतंकवादी पृष्ठभूमि के हैं, ऐसे में आतंकवाद के प्रति अपनी 'जीरो टॉलरेंस' की नीति और अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण के प्रति भारत की वचनबद्धता और उसे पुनः वैश्विक आतंकवाद की नर्सरी बनने से रोकने की प्रतिबद्धता भारत कैसे निभाएगा? यह एक जटिल प्रश्न है। इन प्रश्नों के उत्तर पर ही भारत की सुरक्षा निर्भर है। अगस्त के बाद जितने भी अन्तर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन हुए उन सभी में भारत ने अफगानिस्तान का मुद्दा सफलतापूर्वक उठाया है। 9 सितंबर, 2021 को ब्रिक्स देशों की ऑनलाइन बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि अफगानिस्तान की स्थिरता, शान्ति एवं प्रगति पूरे क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। मोदी जी के प्रयासो का ही परिणाम है कि, ब्रिक्स ने अपने घोषणापत्र में भारत की चिन्ता को स्वीकृति प्रदान करते हुए अफगानिस्तान में आतंकवाद के विरूद्ध लड़ाई को प्राथमिकता देने, अफगानी महिलाओं ,बच्चों एवं अल्पसंख्यकों के मानवाधिकारों की रक्षा करने और अफगानिस्तान को नशीले पदार्थों की तस्करी के केन्द्र में बदलने से रोकने के लिए पारस्परिक सहयोग की बात कही। 17 सितंबर, 2021 को दुशांबे में आयोजित 'शंघाई सहयोग संगठन' की अफगानिस्तान के मुद्दे पर आयोजित एक आउटरीच बैठक में श्री मोदी ने यह सुझाव दिया कि, इस क्षेत्र में आतंकवाद के प्रति 'शून्य सहिष्णुता' एवं 'आचारसंहिता' का विकास करने की तत्काल आवश्यकता है। उन्होने अफगानिस्तान में ड्रग्स, हथियारों एवं मानव तस्करी के साथ वहाँ संभावित मानवीय संकट का उल्लेख करते हुए अफगान लोगों के साथ भारत की एकजुटता के प्रयासों के प्रति वचनबद्धता का भी उल्लेख किया। 24 सितंबर, 2021 को 'क्वाड' की बैठक में भी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने अफगानिस्तान एवं दक्षिण एशिया और भारत–प्रशान्त क्षेत्र की स्थिति पर अपने विचारों को स्पष्टता के साथ सामने रखा। इसी का परिणाम था कि, अपने सम्मेलन के अंत में 'क्वाड' के सभी चारो नेताओं ने तालिबान से अपील की कि, वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव संख्या 2593 का पालन करे, परदे के पीछे छिपकर आतंकवाद का प्रयोग न करे और सीमापार से किए जाने वाले हमलों सहित सभी प्रकार के आतंकी हमलों को करने वाले या करने की योजना बनाने वाले आतंकी समूहों को किसी प्रकार की वित्तीय, रसद या सैन्य मदद न करे। इससे पता चलता है कि, अफगानिस्तान के मुद्दे पर भारत का दृष्टिकोंण पूरी तरह स्पष्ट, पारदर्शी और वैश्विक हितों के परिप्रेक्ष्य में है। भारत तालिबान के शासन में भी वहाँ की जनता को मानवीय आधार पर मदद देने के प्रति वचनबद्ध है। इसे तालिबान शासन को समझना होगा और भारत की सुरक्षा चिन्ताओं के प्रति संवेदनशील बनना होगा।

1991 में तत्कालीन नरसिंह राव सरकार द्वारा घोषित 'लुक ईस्ट पॉलिसी' को मोदी सरकार ने 2014 में **'ऐक्ट ईस्ट पॉलिसी'** में बदलकर इस क्षेत्र के देशों के साथ सांस्कृतिक और व्यापारिक सम्बन्धों को सुदृढ़ बनाने का निर्णय लिया। 2018 में आसियान देशों के साथ हुई बैठक में मोदी ने इस संगठन के सभी देशों के साथ भूमि, जल और डिजिटल कनेक्टिविटी पर बल दिया। आसियान के देश

भारत की भू–राजनीतिक दृष्टि में कितने महत्वपूर्ण हैं, इसका पता इस बात से चलता है कि, 2019 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर मोदी सरकार ने आसियान के सभी 10 देशों के शासनाध्यक्ष/राष्ट्राध्यक्ष को मुख्य अतिथि के रूप में सम्मानित किया। मोदी ने R.C.E.P.(Regional Comprehensive Economic Partenership) को स्वीकार करने का आह्वान 2018 के आसियान के सिंगापुर सम्मेलन में किया था और इसे एशिया–प्रशान्त क्षेत्र की सुरक्षा, सम्पन्नता, व्यापार और निवेश के असीमित संभावनाओं के द्वार खोलने के लिए और क्षेत्र की बेरोजगारी दूर करने के लिए आवश्यक बताया। भारत ने तब इस पहल का स्वागत किया था कि, आशियान के 10 देशों तथा उनके वार्ता–भागीदार 6 राष्ट्रों (चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, भारत, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैण्ड) सहित 16 देशों के बीच होने वाले इस प्रस्तावित समझौते का लक्ष्य विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र बनाना है लेकिन 2019 के अन्त तक भारत की यह समझ में आ गया कि, इस समझौते में शामिल होने से भारत के आर्थिक हित प्रभावित होंगे क्योंकि इस नए आर्थिक संगठन के अधिकांश देशों के साथ भारत का आयात उसके निर्यात की तुलना में बहुत अधिक है जिससे भारत के व्यापार घाटे में भारी वृद्धि होगी, फलतः भारत ने अपनी शंकाओं के निराकरण होने तक इसमें शामिल होनें से इनकार कर दिया। यह मोदी की दृढ़ता का परिचायक है कि **भारत अपने 'मार्मिक राष्ट्रीय हितों' के साथ कोई भी समझौता करने से साफ मना कर दिया।**

मोदी कालीन विदेश नीति की एक बड़ी विशेषता यह है कि, **'सहभागी मूल्यों की संकल्पना'**। पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण संकट, कृषि–उत्पादन में वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय को बढाना, आरगैनिक खेती और ब्ल्यू इकोनॉमी को प्रोत्साहन देना, डिजिटल डिवाइड को पाटना, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन पर्यटन और कोविड–19 के टीकों की वैश्विक उपलब्धता सुनिश्चित करना आदि जैसे मुद्दे आज भारत की अन्तर्राष्ट्रीय प्राथमिकता में आ गए हैं। वैश्विक संगठनों का मंच हो या दो देशों के बीच होने वाली शिखर–वार्ताएं, भारत की प्राथमिकता राजनीतिक–कूटनीतिक या आर्थिक–सैनिक मुद्दों के साथ–साथ सामाजिक जीवन को बेहतर बनाने वाले पहलुओं पर अधिक केन्द्रित रही है, इससे अलग–अलग देशों की जनता को परस्पर एक–दूसरे के नजदीक लाने और अनौपचारिक सम्बन्धों को प्रगाढ करने में मदद मिली है। **ट्रैक–2 डिप्लोमेसी** को मोदी ने एक नयी धार देकर विदेश नीति को अभिनव आयाम दिया है, इसीलिए विदेशों में बसे भारतीयों का हित प्रमुख एजेंडे में आ गया है क्योंकि विदेशों में बसे अप्रवासी भारतीय और भारतीय मूल के विदेशी नागरिक अपने–अपने देश की सरकारों से भारत को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक और रणनीतिक समर्थन दिलाने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। मोदी के अनुसार ये अप्रवासी भारतीय विदेशो में भारत के सांस्कृतिक प्रतिनिधि हैं और इनके कार्य–व्यवहार और दृष्टिकोंण से भारत की नीतियों के प्रति एक स्वीकारात्मक वातावरण तैयार करने में मदद मिली है। मोदी की विदेश यात्राओं में भारत–वंशियों से मिलना और उनके हृदय में भारत के प्रति पल रहे सम्मान व प्यार का भारतीय विदेश नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सकारात्मक रूप से प्रयोग करना मोदी कालीन विदेश नीति का हिस्सा बन चुका है।

विदेश नीति के निर्धारण में एक संघात्मक और लोकतांत्रिक देश की सोच का समावेश करना नरेन्द्र मोदी की एक बड़ी उपलब्धि है। इकाई राज्यों को साथ लेकर उनके राज्य की सीमा से लगती अन्तर्राष्ट्रीय सीमा को पड़ोसी देश से व्यापार और सहयोग की लाइन के रूप में स्वीकार करना, सीमावर्ती राज्यों एवं पड़ोसी देशों के बीच सड़क, रेल और व्यापारिक सम्पर्क बढ़ाना और अन्तर्राष्ट्रीय नीतियाँ बनाते समय राज्यों के महत्वपूर्ण हितों को प्राथमिकता देना **(पैरा–डिप्लोमेसी)** मोदी कालीन विदेश नीति का महत्वपूर्ण पक्ष है। अनेक अन्तर्राष्ट्रीय बैठकों का आयोजन और शिखर वार्ताएं अब राज्यों में भी की जाने लगी हैं, विदेशी पूँजी निवेश को आकर्षित करने में राज्यों की भूमिका को भारत सरकार स्वीकार करने लगी है।[10] इससे भारत की विदेश नीति को अधिक यथार्थवादी बनाने में मदद मिली है।

सन्दर्भ :

1. स्वतंत्रता के बाद भारत ने विदेश नीति के निर्धारण में भी उन्हीं मूल्यों को अपना आधार बनाया जिन मूल्यों को लेकर वह अपने राष्ट्रीय आन्दोलन को खड़ा किया था। सभी राष्ट्रों के साथ समानता और न्याय पर आधारित सम्बन्धों का विकास करना, उपनिवेशों के स्वतंत्रता आन्दोलनों का समर्थन करते हुए भी किसी राष्ट्र के आन्तरिक मामले में हस्तक्षेप न करना, शीत युद्ध और महाशक्तियों की प्रतिस्पर्द्धा से दूर रहकर गुटनिरपेक्षता के रास्ते पर चलना और अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का मध्यस्थता द्वारा निर्धारण आदि नेहरू कालीन भारतीय विदेश नीति के आदर्श थे।
2. आतंकवादियों का पीछा करते हुए दूसरे देश में घुसकर कार्रवाई करने की यह प्रथम घटना है।
3. पाक प्रशिक्षित आतंकवादियों द्वारा किए गए उड़ी हमलें के प्रत्युत्तर में 28–29 सितम्बर, 2016 को पहली बार और पुलवामा हमले के बाद 26 फरवरी, 2019 को दूसरी बार भारत ने पाकिस्तान के विरूद्ध सर्जिकल स्ट्राइक किया था।
4. भारतीय शान्ति सेना 1987–90 तक श्रीलंका रहकर तमिल पृथकतावादी गुटों के विरूद्ध कार्रवाई करती रही और 1990 में राष्ट्रपति प्रेमदासा के आग्रह पर भारतीय प्रधानमंत्री वी.पी. सिंह ने उसे वापस बुला लिया।
5. 1988 मे मालदीव के राष्ट्रपति की तख्ता पलटने की कार्रवाई को भारतीय सेना नें सैन्य हस्तक्षेप करके विफल कर दिया।
6. अमेरिका के बूज एलेन हैमिल्टन ने 2004 में यह संकल्पना प्रस्तुत की थी जिसमें यह बताया गया कि, चीन हिन्द महासागर से लगे तटवर्ती देशों में सैन्य ठिकाने, आधारभूत ढाँचा, आर्थिक गलियारे, बन्दरगाहों का प्रबंधन करने जैसी नीतियों के सहारे पूर्वी एशिया से लेकर पश्चिमी एशिया तक अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ा रहा है। इससे इस क्षेत्र की शान्ति, सुरक्षा और स्थिरता को एक नया खतरा पैदा हो गया है।
7. दीपांजन रॉय चौधरी, 'इण्डिया एक्सटेंड्स डॉलर 50 मिलियन पैकेज टू होस्ट अफ्रीकन यूनियन सम्मिट', इकोनॉमिक टाइम्स, 12 जुलाई, 2019.
8. अमेरिका के साथ इस प्रकार की वार्ता सर्वप्रथम सितंबर 2018 में, जापान के साथ नवंबर 2019 में और ऑस्ट्रेलिया के साथ नवंबर 2021 में प्रारम्भ हुई हैं।
9. एस.400 मिसाइल प्रणाली रूस से लेने के कारण ही अमेरिका ने अपने नाटो सहयोगी तुर्की पर विभिन्न प्रतिबंध लगा दिए थे, पर भारत पर नहीं लगाया।
10. ओब्जा हजारिका, 'इवॉलविंग डाइनेमिक्स ऑफ फेडरलिज्म एण्ड फॉरेन पॉलिसी', इण्डियन फॉरेन अफेयर जर्नल, वॉल्युम 9, नं. 1, जनवरी–मार्च 2014, पृ. 33–45.

***